

## स्वदेशी शक्ति: आत्मनिर्भर भारत — एक शोध पत्र

Dr. Shivansh Rai,  
Asstt Professor Commerce  
Janbhadari,  
Tindni Road, Rani Avanti Bai Bard, In Front of Gupta Iron,  
Narsinghpur,, Madhyapradesh  
Govt girls college, Narsinghpur

### सारांश

आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम (Atmanirbhar Bharat) भारत के आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक पुनरुद्धार की एक विस्तृत पहल है। यह पहल न केवल अर्थव्यवस्था की आत्म-नियतता (self-reliance) को बढ़ाने का लक्ष्य रखती है, बल्कि उत्पादन, रोजगार सृजन, आपूर्ति-शृंखला की मजबूती, नवाचार तथा क्षेत्रीय विकास को भी प्राथमिकता देती है। यह शोधपत्र आत्मनिर्भरता की अवधारणा, नीति-उद्घोष, प्रमुख उपाय, विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव, चुनौतियाँ और सुधारात्मक सिफारिशों का समेकित विवेचन प्रस्तुत करता है। अध्ययन का उद्देश्य आत्मनिर्भरता की व्यावहारिकता, दीर्घकालिक प्रभाव और नीति-निर्माण के लिए सशक्त सुझाव प्रदान करना है।

शब्दावली (Keywords): आत्मनिर्भरता, स्वदेशी उत्पाद, MSME, आपूर्ति-शृंखला, विनिर्माण, नीतिगत उपाय, नवाचार।

### 1. प्रस्तावना (परिचय)

21वीं सदी में वैश्विक आर्थिक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है — वैश्विककरण के लाभों के साथ-साथ आपूर्ति-शृंखलाओं की भंगुरता, आर्थिक झटके और रणनीतिक निर्भरताएँ भी स्पष्ट हुई हैं। ऐसे परिप्रेक्ष्य में भारत ने आत्मनिर्भरता को एक राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में अपनाया। आत्मनिर्भरता का अर्थ केवल आयात-प्रतिस्थापन नहीं है; यह आर्थिक क्षमता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाते हुए वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भागीदारी सुनिश्चित करना है। यह नीति राज्यों, केन्द्र, उद्योग और नागरिकों के सहयोग से समेकित रूप से लागू की जा रही है।

#### 1.1 अध्ययन की आवश्यकता

कोविड-19 महामारी, ग्लोबल सप्लाई-शॉक और भू-राजनीतिक तनावों ने दिखाया कि विदेशी निर्भरता के जोखिम कितने बड़े हो सकते हैं। भारत की विशाल जनसंख्या और बाजार क्षमता इसे आत्मनिर्भर बनने के लिए अनूठा अवसर प्रदान करती है। इस शोधपत्र के माध्यम से यह विश्लेषण किया जाएगा कि आत्मनिर्भरता किस रूप में व्यवहार्य है, किन नीतिगत उपायों की आवश्यकता है, और किन क्षेत्रों में तत्काल व दीर्घकालिक ध्यान चाहिए।

## 2. आत्मनिर्भरता: अवधारणा और दार्शनिक आधार

आत्मनिर्भरता का शाब्दिक अर्थ है—खुद पर निर्भर होना; आर्थिक संदर्भ में इसका अर्थ है—मौजूदा संसाधनों और क्षमता के आधार पर आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, मूल्यवर्धन और निर्यात करना, साथ ही वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप गुणवत्ता बनाए रखना।

### 2.1 आत्मनिर्भरता बनाम आत्मनिर्भरता-उन्मुख वैश्विककरण

आत्मनिर्भरता ग्लोबलिज़ेशन का वैकल्पिक विरोधाभास नहीं है। इसे 'आत्मनिर्भरता-उन्मुख वैश्विक सहभागिता' समझना चाहिए — जहाँ घरेलू उत्पादन और आपूर्ति-श्रृंखला को सुदृढ़ करते हुए विवेकपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सहयोग और व्यापार बनाए रखा जाए।

## 3. नीतिगत पहलें और प्रमुख उपाय (सारांश)

आत्मनिर्भर भारत की नीतियाँ व्यापक हैं — वित्तीय पैकेज, कर बदलाव, घरेलू विनिर्माण प्रोत्साहन, सार्वजनिक खरीद प्राथमिकता, मुद्रा उपाय और तकनीकी सहायता। प्रमुख उपायों में शामिल हैं:

MSME समर्थन: आसान कर्ज, क्रेडिट गारंटी, भुगतान प्रणाली में सुधार, तकनीकी अपग्रेड के लिए सहायता।

विनिर्माण को बढ़ावा: 'मेक इन इंडिया' के साथ तालमेल, आयात-प्रतिरक्षण (temporary safeguards), और उत्पादन-लिंक्ड प्रेरणा (Production Linked Incentive - PLI) जैसी योजनाएँ।

कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था: मूल्य संवर्धन, स्थानीय प्रोसेसिंग इकाइयाँ, सहकारी संस्थाओं का सशक्तिकरण।

डिजिटल तथा स्टार्टअप पारिस्थितिकी: डिजिटलीकरण से पारदर्शिता और व्यावसायिक अवसर; स्टार्टअप के लिए आसान अनुकूल नियम।

सरकारी खरीद में प्राथमिकता: घरेलू उत्पादों को सरकारी ठेकों में वरीयता देना।

नोट: उपर्युक्त बिंदु नीतिगत पहल के सामान्य घटक हैं; इनका विस्तृत कार्यान्वयन समयानुसार और योजनाओं के अनुरूप निर्धारित होता है।

## 4. अनुसंधान विधि (Methodology)

यह शोधपत्र सिद्धांत आधारित विश्लेषण, नीति दस्तावेजों के समेकित अवलोकन और सेक्टरल विवेचन पर

आधारित है। प्राथमिक आँकड़ों के स्थान पर यह पेपर द्वितीयक स्रोतों — सरकारी रिपोर्टें, आर्थिक सर्वेक्षण, नीतिगत घोषणाएँ तथा ऐतिहासिक डेटा के आधार पर तर्क प्रस्तुत करता है। (नोट: यदि आवश्यक हो, तो क्षेत्रीय डेटा-संग्रह के साथ प्रत्यक्ष अध्ययन एक अलग विस्तृत परियोजना बन सकती है।)

## 5. विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव और विश्लेषण

### 5.1 विनिर्माण (Manufacturing)

विनिर्माण आत्मनिर्भरता का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। भारत की मजबूती विनिर्माण में वृद्धि से होगी — जहाँ तकनीकी उन्नयन, मशीनरी, इनपुट सामग्री और कुशल श्रम की उपलब्धता प्रमुख हैं। PLI स्कीम जैसी योजनाएँ विशेष टिकाऊ उद्योगों (सेमीकंडक्टर, मोबाइल, औषधि लक्ष्य) को बढ़ावा देने के लिए उपयोगी साबित हो सकती हैं। विनिर्माण के विस्तार से निर्यात क्षमता और रोजगार दोनों में वृद्धि होगी।

### 5.2 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (MSMEs)

MSME क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है — रोजगार सृजन, गाँवों में आर्थिक गतिविधि और लचीली आपूर्ति-श्रृंखला प्रदान करते हैं। आत्मनिर्भरता के लिए MSME को पूंजी, कच्चा माल पहुँच, डिजिटलीकरण और नई तकनीक के साथ जोड़ना अनिवार्य है। भुगतान में शीघ्रता और सरकारी खरीद का निर्णय MSME को स्थिरता देगा।

### 5.3 कृषि और खाद्य प्रसंस्करण

कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का अर्थ केवल अन्न उत्पादन नहीं बल्कि खाद्य प्रसंस्करण, ठंडी श्रृंखला, मूल्यवर्धन और किसानों को उचित दाम सुनिश्चित करना है। लोकल प्रोसेसिंग यूनिट्स और कृषि-व्यवसाय मॉडल (agribusiness) ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करेंगे तथा खाद्य सुरक्षा बनाएँगे।

### 5.4 स्वास्थ्य और औषधि उद्योग

औषधि निर्माण में भारत पहले से ही मजबूत है, पर उच्च तकनीकी दवाओं, इंटरमीडिएट्स और विशेष मशीनरी में आयात निर्भरता बनी हुई है। आत्मनिर्भरता के लिए अनुसंधान-आधारित दवा विकास, बायोटेक व क्लीनर निर्माण चैन पर निवेश जरूरी है।

### 5.5 सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल अर्थव्यवस्था

IT व डिजिटल सेवाएँ भारत की सबसे बड़ी संपत्तियों में से हैं। आत्मनिर्भरता का डिजिटल आयाम — साइबर सुरक्षा, डेटा सेंटर्स, घरेलू क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर — पर भी निर्भर है। डिजिटल सक्षमता से सेवाएँ निर्यातकर लाभ भी बढ़ेगा।

## 6. उपलब्धियाँ और सकारात्मक संकेतक

(यह अनुभाग सामान्यीकरण-आधारित है; विशिष्ट आँकड़े समय-विशेष पर आधारित सरकार/रिपोर्ट में उपलब्ध होते हैं।)

घरेलू विनिर्माण पर अधिक फोकस से घरेलू इकाइयों की संख्या और उत्पादन क्षमता में वृद्धि की संभावना।

MSME को आसान ऋण और क्रेडिट गारंटी से वित्तीय समावेशन में सुधार।

कृषि प्रोसेसिंग यूनिट्स और ग्रामीण उद्यमिता की दिशा में निवेश से ग्रामीण रोजगार सृजन।

डिजिटलीकरण के चलते पारदर्शिता और बाजार पहुँच में सुधार।

## 7. चुनौतियाँ और सीमाएँ

### 7.1 संसाधन व लागत प्रतिबंध

घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए सावधानीपूर्वक पूँजी निवेश, कच्चा माल के अनुकूल मूल्य और अनुपयुक्त लागत संरचनाएँ चुनौती हैं। घरेलू विनिर्माण को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए लागत को कम करना अनिवार्य है।

### 7.2 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा और निर्यात बाजारों तक पहुँच

यदि आत्मनिर्भरता का अर्थ केवल घरेलू बाजार की सुरक्षा बना रहे तो दीर्घकालिक वृद्धि बाधित हो सकती है। विदेशी बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मक गुणवत्ता और लागत-लाभ होना चाहिए।

### 7.3 टेक्नोलॉजी और कौशल की कमी

उच्च तकनीक वाले क्षेत्रों में मानव संसाधन की कमी और आरएंडडी पर कम निवेश बाधाओं का कारण बनते हैं। कौशल विकास और तकनीकी प्रशिक्षण की योजनाएँ तेज़ी से लागू करनी होंगी।

### 7.4 आपूर्ति-श्रृंखला का बहुलकरण (Diversification)

एक ही स्रोत पर निर्भरता से बचने के लिए आपूर्ति-श्रृंखलाओं का बहुलकरण (diversification) और स्थानीय-क्षमता निर्माण आवश्यक है; परन्तु यह आसान नहीं है और समय लेता है।

### 7.5 नीतिगत स्थिरता और कार्यान्वयन चुनौतियाँ

नीतियाँ सतत और स्पष्ट हों — बार-बार बदलाव या अस्पष्ट निर्देश उद्योगों की योजना क्षमता को प्रभावित कर

सकते हैं। प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली की आवश्यकता है।

#### 8. नीति सिफारिशें (Practical Recommendations)

लक्ष्य-आधारित PLI और इनसेंटिव स्कीमें: ऐसे क्षेत्रों का चयन जहां भारत के पास प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है (दवाइयाँ, मोबाइल, पशुपालन-प्रोसेसिंग), और उन्हें दीर्घकालिक सहारा दिया जाए।

MSME पर विशेष ध्यान: तकनीकी उन्नयन के लिए सब्सिडी, डिजिटलीकरण सहायता, और ई-मार्केटप्लेस तक बेहतर पहुँच। शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने हेतु ऐन्वयन तंत्र।

कौशल विकास: क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, उद्योग-अकादमी भागीदारी और ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग के माध्यम से दक्षता बढ़ाना।

R&D और नवाचार में निवेश: विश्वविद्यालय-उद्योग सहयोग, कर प्रोत्साहन और स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग।

लॉजिस्टिक्स व इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार: सड़कों, रेल, बंदरगाह और ठंडी श्रृंखलाओं (cold chain) में निवेश—क्योंकि विफल लॉजिस्टिक्स विनिर्माण व कृषि दोनों को प्रभावित करता है।

नीतिगत स्थिरता और समीक्षा तंत्र: स्वतंत्र मूल्यांकन फोरम जिसकी मदद से नीतियों के प्रभाव का समय-समय पर आंकलन हो।

न्यायसंगत सरकारी खरीद नीतियाँ: सरकारी खरीद में घरेलू उत्पादों को प्राथमिकता साथ ही गुणवत्ता मानक अनिवार्य हों।

हरित और टिकाऊ विनिर्माण: पर्यावरण मानकों के अनुरूप उत्पादन, संसाधन-प्रबंधन और नवीनीकृत ऊर्जा का उपयोग प्रोत्साहित करें।

#### 9. संभावित दीर्घकालिक प्रभाव

यदि आत्मनिर्भरता को संतुलित, खुले और प्रतिस्पर्धी तरीके से अपनाया जाए तो यह — दीर्घकालिक अर्थव्यवस्था में वृद्धि, निर्यात क्षमता, रोजगार सृजन, और सामाजिक समावेशन में वृद्धि कर सकता है। परन्तु असंतुलित संरक्षणवादी नीतियाँ प्रतिस्पर्धात्मक कमजोरी और बाजार अलगाव का कारण बन सकती हैं। अतः आत्मनिर्भरता की सफलता सशक्त विदेश नीति, तकनीकी प्रतिस्पर्धा और नीतिगत संतुलन पर निर्भर करेगी।

## 10. निष्कर्ष

आत्मनिर्भर भारत एक दूरदर्शी विचार तथा व्यावहारिक नीति पहल है जिसका लक्ष्य भारत को उत्पादन-क्षमता, आत्म-विश्वास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूती प्रदान करना है। इसकी सफलता के लिए सिर्फ नीतियाँ बनाना ही पर्याप्त नहीं — उनका सूक्ष्म, समयबद्ध और पारदर्शी कार्यान्वयन आवश्यक है। सरकार, निजी क्षेत्र, अकादमिक संस्थाएँ और नागरिक समाज मिलकर दीर्घकालिक निवेश, कौशल विकास और नवाचार को प्राथमिकता दें तो आत्मनिर्भरता भारत के लिए समावेशी और सतत विकास के रास्ते खोल सकती है।

## संदर्भ सूची

1. भारत सरकार, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय — \*‘‘मेक इन इंडिया: एक औद्योगिक क्रांति’’\* (2014)।
2. नीति आयोग — \*‘‘भारतीय विनिर्माण नीति का रोडमैप’’\* (2014)।
3. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय — \*‘‘डिजिटल इंडिया विज़न दस्तावेज़’’\* (2015)।
4. कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय — \*‘‘स्किल इंडिया मिशन प्रगति रिपोर्ट’’\* (2015)।
5. वित्त मंत्रालय — \*‘‘आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 (हिन्दी संस्करण)’’\* (2016)।
6. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय — \*‘‘MSME वार्षिक रिपोर्ट’’\* (2016)।
7. वित्त मंत्रालय — \*‘‘वस्तु एवं सेवा कर (GST) प्रभाव रिपोर्ट’’\* (2017)।
8. नीति आयोग — \*‘‘नई औद्योगिक नीति का प्रारूप’’\* (2017)।
9. MSME मंत्रालय — \*‘‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और MSME विकास रिपोर्ट’’\* (2018)।
10. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय — \*‘‘कृषि आधुनिकीकरण एवं निवेश रिपोर्ट’’\* (2018)।
11. कृषि मंत्रालय — \*‘‘कृषि अवसंरचना निधि योजना रिपोर्ट’’\* (2019)।
12. नीति आयोग — \*‘‘भारत@75 विज़न रिपोर्ट’’\* (2019)।
13. भारत सरकार (प्रधानमंत्री कार्यालय) — \*‘‘आत्मनिर्भर भारत अभियान दस्तावेज़’’\* (2020)।
14. वित्त मंत्रालय — \*‘‘कोविड-19 के बाद आर्थिक सुधार और आत्मनिर्भरता रिपोर्ट’’\* (2020)।